CAO
A AO
29/8/11
30

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांकः-प.2(4)शिक्षा-5/2007पार्ट-III जयपुर, दिनांक 29/08/2011

1- आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3- निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

विषयः- राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत राज्य सेवा में नियुक्त अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों का राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 में वेतन निर्धारण किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत राज्य सेवा में नियुक्त गैर-सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों के वेतन का निर्धारण राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत किया जाना है। इस संबंध में यह मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि छठे वेतनमान में वेतन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाना है।

इस विषय पर दिनांक 09/08/2011 को वित्त विभाग में आयोजित बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। उक्त नियमों का नियम 5(vi) निम्नानुसार है:-

> "नियुक्त किये गए समस्त कर्मचारियों का वेतन इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ती के समय यथा आहरित वेतन के आधार पर उनके सरकार में पद ग्रहण करने की तारीख से छटे वेतन आयोग के अनुसार नियत किया जाएगा।"

चूँकि नियमों में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वेतन का निर्धारण राज्य सरकार में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से किया जायेगा (with effect from the date they join in the government under these rules), अतः यह निर्णय लिया गया है कि इन कार्मिकों के वेतन का निर्धारण उस दिनांक से किया जायेगा जिस दिनांक को उन्होंने राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अंतर्गत नियुक्ति उपरांत राज्य सरकार में कार्यभार ग्रहण किया है। अर्थात वेतन का निर्धारण राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के

अन्तर्गत किसी पूर्ववर्ती दिनांक से किया जाकर **नोशनल बैनेफिट (Notional Benefit) नहीं दिया जाना है**। सुलभ संदर्भ हेतु दिनांक 08/09/2011 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण (मिनिट्स) की छाया प्रति संलग्न प्रेषित है।

सभी संबंधित को उपरोक्त निर्णय से सूचित करें तथा निर्देशित करें कि राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत राज्य सेवा में नियुक्त गैर-सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों के वेतन का निर्धारण उक्त निर्णय के अनुसार राज्य सेवा मे कार्यभार ग्रहण करने की तिथी से करें।

29/08/2011

प्रमुख शासन सचिव

संलग्नः दिनांक 08/09/2011 को वित्त विभाग में आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण (मिनिट्स) की छाया प्रति।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर,
2- प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर। कृप्या आपके अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों को सूचित करें तथा तदानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित करें।
3- शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग
4- आयुक्त, कालेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर
5- निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर
6- विशेषाधिकारी वित्त (नियम डिविजन) विभाग

शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/अनु/ई/10–11/समायोजन/46 दिनांक 1/9/11

समस्त उप–निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मुख्य लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Minutes of meeting held in the chamber of ACS, Finance on 09.08.2011 with regard to implementation of ordinance of Rajasthan Voluntary Rural Education Service Rules, 2010 (Rules-2010).

Following Officers were present -

1. Pr. Secretary, Higher Education
2. Pr. Secretary, School Education
3. Commissioner, College Education
4. Secretary, Finance (Budget)
5. OSD, FD (Rules)

Issue No. 1 : Fixation of Pay on Joining the Government Service:-

The issue regarding how the fixation of pay of the employees of Aided Institutions who have joined Government Service under the Rajasthan Voluntary Rural Education Service Rule, 2010 will be made was discussed.

The provision contained in Sub Rule (vi) of Rule 5 of the said rules provides:-

The salary of all the appointed employees shall be fixed on the basis of the salary as drawn at the time of appointment as per the Sixth Pay Commission with effect from the date they join in the government under these rules.

After detailed deliberations there was a considered view that fixation be made as per rules in view of the existing provisions in the Rules,2010.

Issue No. 2: Contribution to Contributory Provident Fund:

The point regarding Contribution to Contributory Provident Fund by the Government is mandatory or not was discussed.

The relevant portion of the provisions of sub rule (ix) under Rule 5 is as under: The persons who are appointed in the government service under these rules shall not be eligible for pension scheme. Contributory Provident Fund Contribution is not deposited by the Non-Government Aided Educational Institutions for the period prior to the date of their joining in the Government after appointment under these rules, shall not be paid by the State Government. They may either continue to be members of the Contributory Provident Fund or they may opt for the Rajasthan Civil Service (Contributory Pension) Rules, 2005. Employer's contribution towards Contributory Provident Fund shall be paid by the government for the period they are in government service.

Rules/6th CPC/Mohan Lalji/A-4 size doc

After detailed deliberations it was decided that the AD may examine the issue whether the Government is bound to Contribute CPF Contribution of these employees. If it is found that Government is not bound to contribute the same as per CPF Rules then suitable amendment may be proposed in the relevant rules, 2010. In such a situation, the employees will be member of Rajasthan Civil Service (Contributory Pension) Rules, 2005.

<u>Regarding balance available in CPF fund</u> of these employees accumulated during their services in the aided institutions the government will not take any liability. The accumulated CPF balance may be lying with the PF Commissioner or in the PD account of the institutions with the Government of Rajasthan or may be with any other institutions. It was decided that the concerned department may collect the information regarding the balance amount. However it is a matter to be settled between the Aided Institutions and employees. The Government will not take any liability on this account.

<u>Issue No.3</u> The issue regarding adjusting the <u>Excess Number of Non Teaching employees on the available vacant posts</u> was discussed in view of the method adopted for adjusting Teaching Staff of Higher Education Department. It was also proposed by the Higher Education Department that Non-Teaching Staff of Higher Education Department may be adjusted in the School Education Department. It was decided that both the department i.e. Higher Education and School Education will prepare list of the number of vacancies District wise and thereafter a suitable view be taken.

The meeting ended with a vote of thanks to the chair.

Officer on Special Duty
FD, (Rules)

Rules/6th CPC/Mu... LaJ/A-4 ...doc